श्री भगवती टी एस्टेट लिमिटेड

बनाम

भारत सरकार और अन्य

3 फरवरी, 1995

[बी. पी. जे. ई. वी. एन. रेड्डी और सुहास सी. सेन, न्यायाधिपतिगण]

केरल निजी वन (निहित और असाइनमेंट) अधिनियम, 1971-संवैधानिक वैधता-धारा 10 द्वारा विचार किए गए उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा करने में विफलता-क्या अधिनियम को अमान्य या असंवैधानिक बनाता है, - अभिनिर्धारित, नहीं - वन (संरक्षण) अधिनियम राज्य अधिनियम के कार्यान्वयन को असंभव नहीं बनाता है।

धारा 8-सी (3) समीक्षा - शब्द प्रासंगिक तिथि या अन्य विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के कारण - अर्थ और दायरा ।

कृषि सुधार के एक उपाय के रूप में जनमान अधिकार पर आयोजित वन भूमि का अधिग्रहण करने के लिये केरल विधानमंडल द्वारा केरल निजी वन (वेस्टिंग एंड असाइनमेंट) अधिनियम, 1971 लागू किए जाने के तुरंत बाद, जिसका प्रभाव सरकार में निजी वनो के स्वामित्व और कब्जे को निहित करने का था, प्रभावित मालिकों ने अधिनियम की संवैधानिक

वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने इस अधिनियम को यह मानते हुए निरस्त कर दिया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 31ए के सुरक्षात्मक दायरे से बाहर है। केरल राज्य ने इस न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया। संविधान पीठ ने अपने आदेश दिनांक 18.9.1973 के द्वारा अपीलों को स्वीकार किया और अधिनियमों की वैधता को बरकरार रखा।

इसके बाद, कुछ प्रभावित मालिकों ने निजी वनों के कुछ हिस्सों को धारा 3 के तहत छूट देने के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन खारिज कर दिये गये, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की जिन्हें भी खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया गया। उपरोक्त सभी कार्यवाहियों के समाप्त होने के बाद, वर्तमान रिट याचिकाएं याचिकाकर्ताओं द्वारा यह घोषणा करने के लिए दायर की गई थीं कि केरल अधिनियम असंवैधानिक है और केरल राज्य और उसके अधिकारियों को सरकार में निहित होने से पहले उनके स्वामित्व वाले निजी वनों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और निजी वनों के कब्जे को पूर्व के मालिकों को बहाल करना, के निर्देश के लिये । याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किया गया मुख्य आधार यह था कि अधिनियम कृषि सुधार के उपाय के रूप में विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम खेती के प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट

श्रेणियो के व्यक्तियो को अर्जित वन भूमिके वितरण पर विचारकरता है और हालांकि अधिनियम लागू होने के बाद से 20 साल से अधिक की अवधि बीत चुकी थी, वन भूमि को धारा 10 द्वारा विचार के अनुसार आवंटित नहीं किया गया था, शायद एक छोटे से हिस्से को छोड़कर; कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन और 1988 में इसके बाद के संशोधन के साथ वन भूमि का आवंटन अनिवार्य हो गया था। चूंकि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि पूरा अधिनियम विफल हो गया है और निजी वनों को उनके पूर्व मालिक को बहाल किया जाना चाहिए।

संबंधित अपील में, जो कि केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिसमें राज्य के द्वारा दायर पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार करते हुये और अपने पहले के फैसले को अपास्त करते हुए, अपीलकर्ता ने कहा कि उसने जनमन में 550 एकड़ भूमि पट्टे पर लेने के लिए एक समझौता किया था, उसे पूरी सीमा तक कब्जे में रखा गया था; कि उसने 10 मई, 1971 से पहले कॉफी और कार्डोमम उगाया था, जिस तारीख को केरल वन (निहित और असाइनमेंट) अधिनियम, 1971 लागू हुआ था; कि वह 1974 से उक्त वृक्षारोपण के लिए भूमि कर और मूल कर का भुगतान कर रहा था, जब से वृक्षारोपण ने उपज देना शुरू किया था। यह तर्क देते हुए कि उक्त सीमा अधिनियम की धारा 2 के तहत

शासन में निहित थी, उसने कहा कि अधिकारियों ने उक्त सीमा का अतिक्रमण किया, जिसके बाद उन्होंने उपयुक्त न्यायाधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 8 के तहत कार्यवाही शुरू की और आरोप लगाया कि उक्त भूमि सरकार में अंतर्गत धारा 3 में निहित नहीं थी, इस कारण से कि अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले यह धारा 2 (एफ) के अर्थ के भीतर एक निजी वन नहीं रह गया था। वन न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के दावे को बरकरार रखा जिसके खिलाफ राज्य ने एक अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। राज्य का यह तर्क कि पट्टा का उक्त समझौता कलेक्टर की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना किया गया था, जैसा कि मद्रास निजी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा आवश्यक है, पट्टा न केवल अमान्य था, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा लीज और कब्जे की डिलीवरीका कथत समझौता सही नहीं था, खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था। पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने वास्तव में दिनांक 7.8.1963 को भूमि पर कब्जा कर लिया था और दिनांक 10.5.1971 से पहले उक्त सीमा को वृक्षारोपण में परिवर्तित कर दिया था। यह आदेश, जिस पर राज्य द्वारा सवाल नहीं उठाया गया है, अंतिम हो गया है।

नवंबर, 1983 में अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करते हुए और मूल अधिनियम में धारा 8-ए के बाद नई धारा 8-बी और 8-डी को शामिल करते हुए 1983 का अध्यादेश संख्या 39 जारी किया गया था। धारा 8-सी

(3) ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए राज्य के लिए सीमा की अवधि बढ़ा दी। राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए एक याचिका प्रासंगिक तिथि या अन्य विवरण प्रस्तुत करने में राज्य की विफलता के आधार पर दायर की। पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार किया गया था ओर अपील को बहाल कर दिया गया। यह अपील, अपील की बहाली के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

रिट याचिका को खारिज करते हुए और अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. हालाँकि केरल सरकार काफी हद तक, केरल निजी वन (निहित और असाइनमेंट) अधिनियम, 1971 के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही है, जैसा कि धारा 10 द्वारा विचार किया गया है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि सरकार की ऐसी विफलता अधिनियम को अमान्य या असंवैधानिक बनाती है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 केरल अधिनियम को अव्यवहारिक नहीं बनाता है। संरक्षण अधिनियम वनों की निकासी को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। पाबंदी पूर्ण नहीं बल्कि योग्य है। यहां तक कि वन (संरक्षण) अधिनियम में 1988 का संशोधन भी राज्य अधिनियम के कार्यान्वयन को असंभव नहीं

बनाता है। धारा 10 में संपूर्ण निजी वन भूमि (अधिनियम के तहत सरकार में निहित) के आवंटन या वितरण पर विचार नहीं करती है, (अधिनियम के तहत सरकार में निहित) बल्कि इसके केवल एक हिस्से पर विचार करती है। । सबसे पहले सरकार को अधिग्रहित वनों के एक उचित हिस्से को कृषि और उसमें उल्लिखित अन्य मामलों को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता है। शेष भूमि व्यक्तियों या सहकारी समितियों को पट्टे या रजिस्ट्री पर दी जानी है। यह सब अभी भी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना किया जा सकता है। [841 - सी-एफ]

केरल राज्य और अन्र बनाम ग्वालियर रेयन्स सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, [1974] 1 एससीआर 671, पर भरोसा व्यक्त किया ।

भीम सिंह बनाम भारत संघ, [1985] पूरक। एससीआर 862, अंतरि स्पष्ट किया ।

2. केरल निजी वन (निहित और असाइनमेंट) अधिनियम, 1971 की धारा 8-सी (3) में शब्द 'प्रासंगिक डेटा या अन्य विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के कारण शब्द का अर्थ है कि यह प्रासंगिक डेटा या विवरण प्रस्तुत करने में विफलता होगी । इसका मतलब केवल एक ही सामग्री या एक ही साक्ष्य पर राय का परिवर्तन नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, जिस आधार पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, वह नहीं बनाया गया

था और इसलिए खंड पीठ के आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकती थी और इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता था। आदेश को रदद करने की तब तक मांग नहीं की गई थी जब तक कि कानून द्वारा निर्दिष्ट एक या दूसरे आधार को सामनेनहीं रखा गया था। [845 - एफ-एच] 835

सिविल मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (सिविल) संख्या 974/1991

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

रिट याचिका (सिविल) संख्या 419/1989

और

सिविल अपील संख्या 120/1986

आर. एफ. नरीमन, ए. एस. नांबियार, ए. एम. सिंघवी, जी. विश्वनाथ अय्यर, जोसेफ वेल्लापल्ली, पी. पी. मल्होत्रा, ए. के. वर्मा, एस. सुकुमारन, पी. डी. त्यागी; जे. बी. डी. एंड कंपनी के लिए। एस. वासुदेवन, पी. के. मनोहर, सुधीर गोपी, एम. एम. कश्यप, सुश्री बेबी कृष्णन, के.वी.विश्वनाथन, एस. आर. सेतिया, के. एस. सोहन, एम. ए. फिरोज, एम. टी. जॉर्ज, एस. डी. शर्मा, वी. के. वर्मा, सी. वी. एस. राव और टी. सी. शर्मा; उपस्थित पक्षकारो के लिए ।

न्यायालय का निर्णय बी.पी. जीवन रेडडी द्वारा दिया गया था।

रिट याचिका संख्या (सिविल) सं. 974/ 1991 और 419/ 1989

केरल निजी वन (निहित और असाइनमेंट) अधिनियम, (1971 का अधिनियम 26), केरल विधानमंडल द्वारा कृषि सुधार के एक उपाय के रूप में जनमन अधिकार पर आयोजित वन भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में इन निजी वनों के मालिकों को दिए जाने वाले किसी भी मुआवजे का प्रावधान नहीं था। सरकार को इस तरह से निहित वन भूमि भूमिहीन किसानों और कृषि मजदूरों को खेती के लिए सौंपने का इरादा था। धारा 10 की उपधारा (1) में कहा गया है कि सरकार पहले अधिनियम के तहत सरकार में निहित निजी वन की ऐसी सीमा तक सेवा प्रदान करेगी जो कृषि को बढ़ावा देने या कृषि आबादी के कल्याण या उसके सहायक उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो। निहित निजी वनों की शेष सीमा किसानों, कृषि मजदूरों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को रजिस्ट्री या पट्टे पर दी जानी थी जो उनकी आजीविका के साधन के तौर पर कृषि करने के इच्छुक हैं और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की अन्य श्रेणियो पर। धारा 11 में यह अपेक्षा की गई थी कि ऐसा कार्य, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर पूरा किया जाएगा।

अधिनियम बनाए जाने के तुरंत बाद, जिसमें निजी जंगलोके स्वामित्व और कब्जे को सरकार में निहित करने का प्रभाव था, प्रभावित

मालिको ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुये केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की। केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने इस अधिनियम को यह मानते हुए निरस्त कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 31ए के सुरक्षात्मक दायरे से बाहर है, जिसका निर्णय ए. आई. आर. 1973 केरल 63 में बताया गया है। केरल राज्य ने इस न्यायालय में उक्त फैसले पर सवाल उठाया, जिसने 18 सितंबर, 1973 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा अपीलों को स्वीकार किया, केरल उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त कर दिया और अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। इस न्यायालय के निर्णय का प्रकाशन केरल राज्य व एक अन्य बनाम ग्वालियर रेयन्स सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, [1974] 1 एस. सी. आर. 671 में किया गया है। संविधान पीठ का मुख्य निर्णय पालेकर, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था, जबकि वी. आर. कृष्णा अययर, न्यायाधिपति ने एक अलग सहमति वाला निर्णय दिया था।

इस अदालत के फैसले के बाद केरल सरकार ने वन क्षेत्रों का अध्ययन करने और निहित वनों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कुछ उच्च अधिकारियों वाली एक समिति का गठन किया। सरकार का कहना है कि उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, उसने समनुदेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि अधिनियम के तहत सरकार को निहित कुल हेक्टेयर में से 4000

हेक्टेयर आदिवासियों, सहकारी समितियों और कृषि सुधारों को दिया गया है और 6,878 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र राजस्व विभाग को वितरित करने के लिए सौंप दिया गया है। कहा जाता है कि 8000 हेक्टेयर का क्षेत्र अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है।

जबकि, संसद ने संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।।। की प्रविष्टि 17 ए के आधार पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अधिनियमित किया। यह याद किया जा सकता है कि वनों का विषय मूल रूप से सूची-।। में था, लेकिन संविधान के 42 वें (संशोधन) अधिनियम के आधार पर इसे सूची-।। से हटा दिया गया और सूची-।।। में डाल दिया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान है कि "(किसी राज्य में उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा, कोई भी आदेश नहीं देगा, जिसमें निर्देश दिया गया हो कि (i) कोई भी आरक्षित वन (उस राज्य में उस समय लागू किसी कानून में" आरक्षित वन "अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर) या उसका कोई भी हिस्सा, आरक्षित होना बंद हो जायेगा; (ii) कि किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग किसी गैर-वन उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। धारा 2 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि धारा 2 के प्रयोजन के लिए 'गैर-वन उद्देश्यों' का अर्थ है किसी भी वन भूमि या उसके हिस्से को तोड़ना या साफ़

करना, जो पुनर्निर्धारण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए है। संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन ने निश्चित रूप से केरल अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के रास्ते में बाधा उत्पन्न की क्योंकि मुख्य उददेश्यो में से एक खेती के लिये उक्त वन भूमि का आवंटन था और खेती का मतलब वन विकास की मंजूरी है ओर केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी कोई मंजूरी संभव नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वन भूमि को संभवतः वन विकास के रूप में आवंटित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया गया था। वर्ष 1988 में, संसद ने वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी निजी व्यक्ति या किसी भी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संगठन को पट्टे पर देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं है। धारा 2 के स्पष्टीकरण को भी प्रतिस्थापित किया गया था जो अन्य बातों के साथ कहता है कि 'गैर-वन उद्देश्य' का अर्थ पुनर्वनीकरण के अलावा कोई अन्य उद्देश्य है। जो भी हो, तथ्य यह है कि केरल अधिनियम के तहत अधिग्रहित निजी वनो को अब तक आरक्षित या आवंटित नहीं किया जा सका है, जैसा कि अधिनियम की धारा 10 में विचार किया गया हे, उपर उल्लिखित एक छोटे से हिस्से के आवंटन को छोडकर ।

अधिनियम की वैधता को सफलतापूर्वक चुनौती देने में विफल रहने के कारण, कुछ प्रभावित मालिकों ने धारा 3 के तहत निजी वनों के कुछ हिस्सों की छूट के लिए आवेदन किया। उनके आवेदन खारिज कर दिए गए, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। उनमें से कुछ ने विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसे खारिज कर दिया गया। यह तब है जब उनमें से कुछ इन रिट याचिकाओं के साथ आगे आए हैं।

इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत इस घोषणा के लिए है कि केरल अधिनियम असंवैधानिक है और केरल राज्य और उसके अधिकारियों को सरकार में निहित होने से पहले उनके स्वामित्व वाले निजी वनों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने से रोकने के निर्देश के लिये है। यह भी प्रार्थना की जाती है कि निजी वनों का अधिकार पूर्व के मालिकों को बहाल किया जाए। इन रिट याचिकाओं के समर्थन में आग्रह किया गया मुख्य आधार यह है; यह अधिनियम कृषि सुधार का एक उपाय है; क्योंकि इसे कृषि सुधार का एक उपाय माना जाता था, इसे संविधान के अनुच्छेद 31ए द्वारा संरक्षित माना गया था, हालांकि इसमें वंचित मालिको को मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। यह अधिनियम खेती के प्रयोजनो के लिये व्यक्तियो की निर्दिष्ट श्रेणियो को अर्जितवन भूमि के वितरण पर विचार करता है। यद्यपि उक्त अधिनियम

को लागू किए हुए बीस वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है, लेकिन शायद एक छोटे से हिस्से को छोड़कर, वन भूमि को धारा 10 द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है। सरकार वन संपदा से वैसे ही आय प्राप्त कर रही है जैसे मालिक सरकार में निहित होने से पहले कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए उक्त वन भूमि का उपयोग कर रही है। यह वास्तव में भूमि के वितरण/आवंटन में रुचि नहीं रखता है। इसके अलावा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन के साथ, वन भूमि का आवंटन असंभव हो गया है। यह मान लेना व्यर्थ है कि केंद्र सरकार इतने बड़े वनों के क्षेत्र को साफ करने की अनुमति देगी। चूंकि इतनी बड़ी भूमि से वन विकास की मंजूरी से राज्य की पारिस्थिति की और पर्यावरण प्रभावित होगा, इसलिए केंद्र सरकार कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करना असंभव हो गया है। चूंकि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया है, इसलिए पूरा अधिनियम विफल हो जाता है और निजी वनों को उनके पूर्व मालिकों को बहाल किया जाना चाहिए। संविधान के 40 वें (संशोधन) अधिनियम द्वारा अधिनियम को संविधान की नौंवी अनुसूची (एस.आई. संख्या 146 पर) में शामिल करना, किसी भी तरह से उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के रास्ते में नहीं आता है। भारती संशोधन अधिनियम के बाद इसे न केवल नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बल्कि अनुच्छेद

31बी द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा याचिकाकर्ताओ के निवेदन का कोई जवाब नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे कहा कि केरल अधिनियम और वन (संरक्षण) अधिनियम एक-दूसरे के लिए प्रतिकूल हैं और किसी भी स्थिति में जब तक केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी नहीं दी जाती, तब तक विसंगति बनी रहती है।

केरल अधिनियम की धारा 3 नियत दिन पर राज्य के सभी निजी वनों को सरकार में निहित करती है। धारा 2 के खंड -ए के अनुसार, "नियत दिवस" का मतलब मई, 1971 का 10वां दिन अभिप्रेत है। प्रभावित मालिकों द्वारा अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था लेकिन जैसा कि यहां पहले कहा गया है, वे अंतत: विफल रहे। अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए इस अदालत का निर्णय सितंबर 1973 में दिया गया था। लगभग सोलह वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद, कुछ मालिक वर्तमान रिट याचिकाओं के साथ आगे आए हैं जो फिर से उक्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर आक्षेप करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अलग आधार पर। अब मुख्य आधार यह है कि अधिग्रहित वन भूमि को बीस साल से अधिक समय बीतने के बावजूद अधिनियम की धारा 10 द्वारा विचार के अनुसार आवंटित नहीं किया गया है, अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसद द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम का अधिनियमन वर्ष 1980

में और 1988 में इसके बाद के संशोधन ने अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति को असंभव बना दिया है। दूसरे शब्दों में, वे कहते हैं, यह अधिनियम कृषि सुधार के उपाय के रूप में विफल रहा है। यह निजी संपत्ति को ज़ब्त करने का एक मात्र और सरासर उपाय निकला है। अधिनियम में एक समग्र योजना शामिल है; यदि एक भाग विफल हो जाता है, तो संपूर्ण योजना/अधिनियम विफल हो जाती है, इसे प्रस्तुत किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि यह भी प्रतीत नहीं होता है कि केरल सरकार ने कभी भी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए आवेदन किया था, जो उनके अनुसार तथ्य यह स्थापित करता है कि सरकार अधिनियम को लागू करने के लिए कभी भी इच्छुक नहीं थी। वे कहते हैं कि चूंकि यह वन संपदा पर काफी निर्भर है और इससे आय प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसका भूमि वितरित करने का कोई झुकाव नहीं है। ग्वालियर रायन में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की राय में निम्नलिखित टिप्पणियो पर मजबूत भरोसा रखा गया है:

"तथापि, हम यहाँ यह इंगित कर सकते हैं कि यह सुनिश्चित करने में कि क्या विवादित अधिनियम कृषि सुधार के लिए एक खाका तैयार करता है, न्यायालय वैधानिक प्रस्ताव के सार को देखेगा, न कि केवल इसके बाहरी रूप को। न्यायालय यह देखने के लिए बारीकी से अध्ययन

करेगा कि क्या कानून केवल कृषि सुधार का मुखौटा पहनता है या यह वास्तविकता में ऐसा है। एक लेबल किसी क़ानून को संवैधानिक सीमाओ के चंगुल से नहीं बचा सकता है यदि इसके द्वारा परिकल्पित कृषि सुधार "एक चिढ़ाने वाला भ्रम या वास्तविकता का वादा" है। न्यायालय को भी कृषि सुधार की एक योजना को स्वीकार करने में ऐसा भोलाभाला नहीं होना चाहिये, जबकि यह एक मौखिक दिखावा के अलावा और कुद नहीं है, लेकिन साथ ही न्यायालय को ऐसी योजना को अस्वीकार करने के लिये इतना चतुर भी नहीं होना चाहिये क्योंकि वह योजनाकी समझदारीयाइसकी तकनीकी सुदृढता से संतुष्ट नहीं है। क्या राज्य मुआवजेके बिना किसी औद्योगिक इकाई या व्यावसायिक उपक्रम को अपने कब्जे में ले सकता है और यह कहकर अनुच्छेद 31ए के संरक्षण का दावा कर सकता है कि ऐसी औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक उपक्रम से उत्पन्न होने वाले लाभ का उपयोग कृषि या ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण के लिये किया जायेगा? इस तरह का अधिग्रहण स्पष्ट रूप से कृषि सुधार की योना को आगे बढाने के लिये अधिग्रहण नही होगा क्योंकि प्राप्त विषय वस्तु और कृषि सुधार के लिये उसके उपयोगके बीच कोई सीधा संबंध नहीं होगा। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि अधिग्रहित संपत्ति की आय का उपयोग कृषि सुधार के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। इस तरह के सुधार को अंजाम देने के लिये संपत्ति स्वंय ही अधिग्रहित की जानी चाहिए। यह आवश्यकता

वर्तमान मामले में संतुष्ट है क्योंकि धारा 10 के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि का उपयोग "कृषि को बढ़ावा देने या कृषि आबादी के कल्याण के लिए या उसके सहायक उद्देश्यों के लिए" किया जाना है। हमें नहीं लगता कि केवल यह प्रदान करना पर्याप्त होगा कि वनों की उपज से होने वाली आय का उपयोग कृषि को बढ़ावा देने या कृषि आबादी के कल्याण के लिए किया जायेगा, लेकिन वन भूमि का उपयोग इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए एक उपाय होता, हालांकि इस निर्देश के साथ कि राजस्व में इस तरह की वृद्धि केवल कृषि को बढ़ावा देने या कृषि जनसंख्या का कल्याण के उद्देश्यों पर खर्च की जायेगी। लेकिन यहाँ धारा 10 को पढ़ने पर स्पष्ट है कि वन और जंगलो से होने वाली आय को कृषि के संवर्धन या कृषि आबादी के कल्याण या कृषि सुधार से निकटता से संबंधित सहायक उपयोगों के लिए समर्पित या निर्देशित किया जाना है। कृषि सुधार की योजना का विवरण जिसके अधीन अधिग्रहित वनों को रखा जाएगा, स्पष्ट रूप से क़ानून में सन्निहित नहीं किया जा सकता है और उन्हें उन नियमों द्वारा प्रदान किया जाना है जो धारा 17 के तहत कानून के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए जाने हैं। यह कहा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई नियम नहीं बनाए जा सके, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय में याचिका लंबित होने पर अधिनियम के कार्यान्वयन के खिलाफ रोक थी और उसके बाद केरल

उच्च न्यायालय के फैसले से अधिनियम को अधिकारातीत और अमान्य घोषित कर दिया गया था, जो हमारे समक्ष अपील के तहत है। अब जब इस अधिनियम को हमारे द्वारा संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया जा रहा है, तो राज्य सरकार को कृषि सुधार के सटीक कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए नियम बनाने होंगे, जिसे लागू करने का इरादा है। वन मालिकों के वकील ने हमारे सामने आशंका व्यक्त की है कि राज्य सरकार वनों को कई वर्षो तक वैसे ही रख सकती है जैसे वे लंबे समय से हैं और उन पर उगाई जाने वाली लकड़ी को काटकर और बेचकर राज्य के राजस्व को बढ़ा सकती है और इस प्रकारअनुछेद 31-ए के तर्क को पराजित करता है। लेकिन इस आशंका का कोई आधार या औचित्य नहीं है क्योंकि हमारा विचार है कि कृषि परियोजना को राज्य सरकार द्वारा दो साल की निर्धारित अवधि के भीतर या उसके बाद किसी भी उचित समय के भीतर ठोस रूप से स्पष्ट करना होगा। यदि राज्य सरकार धारा 10 में विचारित कृषि सुधार के निश्चित प्रस्ताव को उचित समय के भीतर लागू किए बिना केवल जंगलों में उगाई जाने वाली लकड़ी को काटकर और बेचकर पैसा कमाती रहती है तो यह कानून का उल्लंघन होगा और ऐसे मामले में पीडित पक्ष कानूनी कार्यवाही करने के लिये सक्षम होंगे और राज्य को वैधानिक वादा पूरा करनेके लिये मजबूर करेंगे और धारा 10 के संदर्भ में कार्य करने के लिये और अगर जंगलों को धारा 10 के दायरे से बाहर

उपयोग के लिये ले जाया जाता है तो अदालत राज्य को ऐसे नाजायज कारनामो से रोक सकती है।"

हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं जबकि हम इस तर्क के बल को देखते हैं कि केरल सरकार, काफी हद तक, धारा 10 द्वारा यथा अनुध्यात अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में काफी हद तक विफल रही है, हम यह मानने के लिए कोई आधार नहीं देखते हैं कि सरकार की ऐसी विफलता अधिनियम को अमान्य बनाती है। यह कभी नहीं माना गया है कि कोई भी अदालत किसी अधिनियम के उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा करने में विफल होने पर अधिनियम को अमान्य या असंवैधानिक बना देती है। कानून को ऐसा कोई सिद्धांत ज्ञात नहीं है। हम इस बात से सहमत होने में भी असमर्थ हैं कि वन (संरक्षण) अधिनियम ने केरल अधिनियम को अव्यवहारिक बना दिया है। संरक्षण अधिनियम वनों की सफाई को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। प्रतिबंध पूर्ण नहीं बल्कि योग्य है। यहां तक कि वन (संरक्षण) अधिनियम में 1988 का संशोधन भी राज्य अधिनियम के कार्यान्वयन को असंभव नहीं बनाता है। यह याद रखा जा सकता है कि धारा 10 में पूरी निजी वन भूमि (अधिनियम के तहत सरकार को निहित) के आवंटन या वितरण पर विचार नहीं करती है,

बल्कि इसके केवल एक हिस्से पर विचार करती है। सबसे पहले, इसके लिए सरकार से अधिग्रहित वनों के एक उपयुक्त हिस्से को कृषि और उसमें उल्लिखित अन्य मामलों को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता है। शेष भूमि व्यक्तियों या सहकारी संस्थाओं को पट्टे या रजिस्ट्री पर दी जानी है। यह सब अभी भी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की इस दलील से सहमत होना भी संभव नहीं है कि केंद्र सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 के तहत पूर्व अनुमोदन को अस्वीकार करने के लिए बाध्य है। हम केंद्र सरकार के लिए निर्णय नहीं ले सकते हैं और न ही हम ऐसा मान सकते हैं और उस आधार पर अधिनियम को अमान्य कर सकते हैं।

वास्तव में, ग्वालियर रेयन्स में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की राय में पहले उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियां ही याचिकाकर्ताओं के तर्क के खिलाफ हैं। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि यदि राज्य सरकार एक उचित अवधि के भीतर धारा 10 के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहती है, यह पीडित पक्षो को कानूनी कार्यवाही करने के लिये सक्षम करेगा, जिससे राज्य को वैधानिक आधार को पूरा करने और धारा 10 के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य किया जा सके। याचिकाकर्ताओं के विद्धान न्यायाधीश द्वारा विचार किये गये पीडित पक्षो के रूप में नहीं माना जा सकता है। संदर्भ में,

अभिव्यक्ति इसका मतलब है कि वे व्यक्ति जो धारा 10 के अनुसार वन भूमि आरक्षित या आवंटित किये जाने पर लाभ प्राप्त करते है। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि "यदि वनो को धारा 10 के दायरे से बाहर उपयोग के लिये ले जाया जाता है तो अदालत राज्य को ऐसे नाजायज कारनामे करने से रोक सकती है। यदि कोई उचित पक्ष अदालत में आता है, तो वह सब किया जा सकता है, जो केरल सरकार को धारा 10 के अनुसार कार्य करके वैधानिक वादे को पूरा करने का निर्देश देगा।

हमें यह भी उल्लेख करना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं के वकील इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के किसी भी निर्णय को हमारे ध्यान में नहीं ला सके, जहां इस तरह के अधिग्रहण को इस आधार पर अमान्य कर दिया गया था कि अधिग्रहण के उद्देश्य एक उचित अवधि के भीतर हासिल नहीं किये गये थे या अपने उददेश्यो के कार्यान्वयन के लिय कदम उठाने से पहले किसी अन्य प्राधिकरण की अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भीम सिंह जी बनाम भारत संघ, [1985] पूरक एस. सी. आर. 862 में कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि नौंवी अनुसूची में शामिल करने से कोई अधिनियम नहीं बचता यदि यह संविधान की मूल संरचना को नुकसान

पहुंचाता है। हमने यहां उपर जो कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए हमें यहां उन टिप्पणियो की कोई प्रासंगिकता नही दिखती।

उपरोक्त दो कारणों से, रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती हैं। कोई खर्चा नहीं।

सिविल अपील सं 120/1986 :

यह अपील केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है जिसमें राज्य द्वारा दायर समीक्षा याचिका को स्वीकार किया गया था और 3 अगस्त 1983 के अपने पहले के फैसले को अपास्त किया गया था।

अपीलार्थी का कहना है कि उसने 7 अगस्त 1963 को कर्ता और वेंकनाडु कोविकम के वरिष्ठ सदस्य के साथ नीलमाला पालघाट जिले में स्थित जनमन में उक्त कोविकल की 550 एकड जमीन पटटै पर लेने के लिये एम समझौता किया था। उसका कहना है कि उसने पूरीसीमा पर कब्जा कर लिया था और उसे 10 मई 1971 से पहले 215 एकड में कॉफी और 225 एकड में कार्डोमम की खेती की थी, जिस दिन केरल वन (निहित और असाइनमेंट) अधिनियम, 1971 लागू हुआ था। अपीलार्थी आगे कहता है कि वह 1974 से उक्त वृक्षारोपण के लिए भूमि कर और मूल कर का भुगतान कर रहे हैं, यानी जब से वृक्षारोपण से उपज शुरू हुई है। यह तर्क देते हुए कि उक्त सीमा अधिनियम की धारा 2 के तहत सरकार में निहित थी, वे कहते हैं कि अधिकारियों ने उक्त सीमा का अतिक्रमण किया,

जिसके बाद उन्होंने ओ.ए. संख्या 139/1977 उपयुक्त न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 8 के तहत प्रस्तुत की। न्यायाधिकरण के समक्ष उनका तर्क था कि उक्त भूमि धारा 3 के तहत सरकार में निहित नहीं थी क्योंकि अधिनियम के लागू होने की तारीख से बहुत पहले यह धारा 2 (च) के अर्थ में एक निजी वन नहीं रह गया था। 25 मई, 1981 के अपने आदेश द्वारा वन न्यायाधिकरण ने उस अपीलार्थी के दावे को बरकरार रखा, जिसके विरुद्ध केरल राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील,एम. एफ. ए. सं. 1/1982 दायर की। खंडपीठ जिसने अपील की सुनवाई की, ने 3 अगस्त, 1983 को न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए इसे खारिज कर दिया। खंडपीठ के समक्ष राज्य द्वारा आग्रह की गई दलीलों में से एक यह थी कि पट्टा का उक्त समझौता कलेक्टर की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना किया गया था, जैसा कि मद्रास निजी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा आवश्यक है, पट्टा न केवल अमान्य है, बल्कि उक्त तथ्य यह भी स्थापित करता है कि अपीलकर्ता द्वारा लीज और कब्जे की डिलीवरी का कथित समझौता सही नहीं है। इस तर्क को खंडपीठ ने ए-20, विद्धान जिला न्यायाधीश, पालघाट की फाइल पर ओ. एस. 1/64 में नियुक्त रिसीवर की रिपोर्ट और औपचारिक पट्टा विलेख प्रदर्श ए-21 जो कि वर्ष 1973 में पट्टा समझौते के अनुसार निष्पादित किया गया, पर भरोसा करते हुये खारिज कर दिया था। उपरोक्त के अलावा, खंडपीठ ने प्रदर्श पी.8 किराया रसीद

दिनांक 9 नवंबर 1963 कोविलकम के करियास्थ द्वारा अपीलकर्ता को जारी पर भी भरोसा किया। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने वास्तव में 7 अगस्त, 1963 को उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था और 10 मई, 1971 से पहले उक्त सीमा को वृक्षारोपण में परिवर्तित कर दिया था। यह आदेश अंतिम हो जाता है, जिस पर राज्य द्वारा अदालत में या अन्यथा सवाल नहीं उठाया गया है।

18 नवंबर, 1983 को, केरल के राज्यपाल ने 1983 के अध्यादेश संख्या 39 के तहत एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें अधिनियम की धारा 8 में संशोधन किया गया और मूल अधिनियम मे धारा 8 ए के बाद नई धारा 8-बी, 8-सी और 8-डी शामिल की गई। धारा 8-बी ने राज्य के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन करने की सीमा की अवधि को उसमें निर्दिष्ट आधारों पर बढ़ा दिया। धारा 8-सी (3), जो हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए राज्य के लिए सीमा की अवधि को उसमें निर्दिष्ट आधारों पर बढ़ा दिया। इस मामले के उददेश के लिये, इस मामले में, धारा 8-सी की उप-धारा (3) पर ध्यान देना पर्याप्त है। वह इस प्रकार हैः

"(3) इस अधिनियम में या परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केंद्रीय अधिनियम 36) या तत्समय लागू किसी अन्य कानून में, या किसी

न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुये भी, सरकार, यदि वे संतुष्ट है कि किसी भी कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निर्णय या आदेश (उपधारा 2 में निर्दिष्ट आदेश के अलावा), किसी भी भूमि से संबंधित है जो एक निजी वन है और ऐसा निर्णय या आदेश तथ्यो को दबाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने या प्रासंगिक डेटा या अन्य विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के कारण पारित किया गया है या ऐसे निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील आवेदन करने और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने मे देरी के कारण दायर नहीं की जा सकी है। केरल निजी वन (निहित और समनुदेशन) संशोधन अध्यादेश, 1983 के प्रारंभ होने के 6 महीने के भीतर, ऐसे निर्णय या आदेश की समीक्षा के लिये उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है।"

(पेपर बुक से उद्धृत)

हमारे ध्यान में लाया गया है कि मूल अध्यादेश की समाप्ति के बाद, समय समय पर क्रमिक अध्यादेश जारी किये गये थे। जो भी हो, धारा 8-सी (3) का लाभ उठाते हुए केरल राज्य ने 3 अगस्त 1983 के उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लियेएक याचिका दायर की। इसे थॉमेन, न्यायाधिपति के समक्ष लगाया गया था, जो खंडपीठ के दो सदस्यो में से एक थे, ने 3 अगस्त 1983 को अपील खारिज कर दी थी। विद्वान न्यायाधीश ने पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार कर लिया और 17 सितंबर,

1985 के विवादित आदेश के तहत दायर करने के लिए अपील को बहाल कर दिया।

धारा 8-सी (3) को पढ़ने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय निम्नलिखित तीन आधारों में से किसी पर भी अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है:

(1) कि ऐसा निर्णय या आदेश तयिो को दबाने या गलत तरीके से पेश करने के कारण पातिर किया गया है;

(2) कि ऐसा निर्णय या आदेश प्रासंगिक तिथिया आदेश विवरण प्रस्तुत करने में विफलताके कारण पारित किया गया है

(3) कि ऐसे निर्णय या आदेश के लिये आवेदन करने या उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने मे देरी के कारण ऐसे निर्णय या आदेश के विरूद्ध अपील दायर नहीं की जा सकती है।

राज्य द्वारा दायर समीक्षा याचिका दूसरे आधार पर आधारित थी, अर्थात, प्रासंगिक आंकड़ा या अन्य विवरण प्रस्तुत करने में राज्य की विफलता, यह तथ्य विशेष रूप से आक्षेपित आदेश के पहले पैराग्राफ में उल्लेखित है। विद्वान न्यायाधीश के समक्ष सरकारी वकील की ओर से तर्क दिया गया था कि इसे उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था कि 1963 में प्रदर्श ए-5 ए-5 के निष्पादन से पहले, मद्रास निजी वन

संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत आवश्यक जिला कलेक्टर की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इस तर्क का आग्रह डिवीजन बेंच के समक्ष किया गया था जब उसने अपील पर सुनवाई की थी और इसे खारिज कर दिया था। फिर भी विद्वान न्यायाधीश ने मद्रास अधिनियम की धारा 3 को नोटिस करने के बाद कहा कि उक्त प्रावधान के अनुसार जिला कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी अलगाव शून्य और अमान्य है और उक्त परिस्थिति विचार के लिए कई सवाल उठाती है, अर्थात्, क्या पट्टा समझौता मद्रास अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के भीतर अलगाव के बराबर है और यदि ऐसा है तो क्या यह कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के साथ किया गया था और आगे क्या ऐसी पूर्व अनुमति के बिना ऐसा अलगाव भूमि को केरल अधिनियम के दायरे से बाहर करने के लिए एक आधार का गठन कर सकता है और कुछ अन्य निश्चित प्रश्न। प्रासंगिकता यह है कि विद्वान न्यायाधीश ने यह नहीं कहा या पाया कि उच्च न्यायालय का आदेश प्रासंगिक डेटा या अन्य विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के कारण किया गया था, या दूषित किया गया था। वास्तव में, राज्य द्वारा समीक्षा याचिका में न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई डेटा या विवरण नहीं रखा गया था। उसी सामग्री पर, जो अपील में अभिलेख पर थी, विवादित आदेश दिया गया है। हमारी राय है कि "प्रासंगिक डेटा या अन्य विवरणों का उत्पादन

करने में विफलता के कारण" शब्दों का वही अर्थ है जो वे कहते हैं। यह प्रासंगिक तिथि या विवरण प्रस्तुत करने में विफलता होनी चाहिए; इसका मतलब केवल एक ही सामग्री या एक ही साक्ष्य पर राय बदलना नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि जिस आधार पर पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई थी, वह नहीं बनाया गया था और इसलिए 3 अगस्त, 1983 के आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकती थी और उसे अपास्त नहीं किया जा सकता था। यह सच है कि विवादित आदेश के तहत विद्वान न्यायाधीश ने 3 अगस्त 1983 के आदेश को रदद करनेके बाद अपील को दायरकरने के लिय बहाल कर दिया है, जिसका अर्थ था कि अपील की सुनवाई अभी बाकी है, लेकिन, हमारी राय में, इसे अपास्त करना ही सही है। यह सच है कि आक्षेपित आदेश के तहत विद्धान न्यायाधीश ने दिनांक 3 अगस्त, 1983 के आदेश को अपास्त करनेकके बाद केवल अपील दायर करने के लिये बहाल किया है, जिसका अर्थ है कि अपील पर अभी सुनवाई होनी हे, लेकिन हमारी राय में दिनांक 3.8.1983 के आदेश को खारिज कर दिया गया है तब तक नहीं बहाल किया जा सकता जब तक कि कानून द्वारा निर्दिष्ट एक या अन्य आधार तैयार नहीं किया गया हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, इस अपील में उठाये गये अन्य प्रश्न, जैसे कि केरल अधिनियम में उपरोक्त धाराओ को सम्मिलितकरने वाले क्रमिक अध्यादेशों की वैधता,पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

तदनुसार, हम, अपील को स्वीकार करते है और विवादित फैसले को अपास्त करते है और खंडपीठ के 3 अगस्त, 1983 के डिवीजन बेंच के फैसले को बहाल करते है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि यहां दिये गये आदेश के अनुसार, अपील में कोई भी आदेश पारित किया जाता है, चाहे अंतरिम हो या अंतिम, वे समान रूप से अपास्त किये जायेंगे। कोई खर्चा नहीं।

याचिका खारिज की गई और अपील स्वीकार की गई।

आर.ए.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।